भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2287

शुक्रवार, 07 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

औद्योगिक कॉरिडोर तथा औद्योगिक पार्कों की प्रगति की समीक्षा

2287. श्री महेंद्र भट्ट:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार 'पीएम गतिशक्ति' पहल के अंतर्गत विकसित औद्योगिक कॉरिडोर, औद्योगिक पार्कों तथा औद्योगिक अवसंरचना की प्रगति की समीक्षा कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो उत्तराखंड सहित राज्यों में संस्वीकृत तथा वर्तमान में प्रगति पर चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): जी, हां, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी) के माध्यम से राज्य सरकारों, कार्यान्वयन एजेंसियों और अन्य हितधारकों के समन्वय से राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के अंतर्गत परियोजनाओं की प्रगति की आवधिक समीक्षा करता है। माननीय वित्त मंत्री (एचएफएम) की अध्यक्षता में एक शीर्ष मॉनिटरिंग प्राधिकरण, समय-समय पर एनआईसीडीआईटी के कार्यकलापों और औद्योगिक कॉरिडोर परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करता है। इसके अलावा, परियोजना कार्यान्वयन में तेजी लाने और मुद्दों का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए परियोजना मॉनिटरिंग समूह (पीएमजी) और 'प्रगति' तंत्र के तहत परियोजनाओं की मॉनिटरिंग की जाती है। इसके अलावा, परियोजना का प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर और एसपीवी द्वारा नियमित समीक्षा बैठकें, स्थल दौरे, माइलस्टोन ट्रैकिंग तथा भौतिक और वित्तीय प्रगति की मॉनिटरिंग की जाती है।

(ख): अभी तक, भारत सरकार ने 7 औद्योगिक कॉरिडोर सहित 13 राज्यों में 20 औद्योगिक कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसका ब्यौरा **अनुबंध-I** में संलग्न

है। इसके अलावा, पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (पीएमजीएस-एनएमपी) फ्रेमवर्क के तहत गठित नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी), आयोजना चरण में एकीकृत आयोजना, मल्टी-मोडैलिटी, इंटर-मोडैलिटी, प्रयासों के परस्पर समन्वय, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, परियोजना स्थल पर और उसके आसपास व्यापक विकास, डाटा आधारित निर्णय लेने आदि को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं का मूल्यांकन करता है। अब तक, लगभग 18.66 लाख करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली 396 अवसंरचना परियोजनाओं का एनपीजी तंत्र के माध्यम से मूल्यांकन किया गया है। इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 07.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2287 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

क्रम सं.	परियोजना और कॉरिडोर का नाम	कुल क्षेत्रफल (एकड़)	परियोजना लागत (रु. करोड़ में)
1.	धोलेरा, गुजरात - डीएमआईसी	5,570	₹ 2,784 करोड़
2.	शेंद्रा, महाराष्ट्र - डीएमआईसी	2,073	₹ 1,533 करोड़
	बिदकिन, महाराष्ट्र - डीएमआईसी	7,855	₹ 6,414 करोड़
3.	आईआईटी- ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश - डीएमआईसी	747	₹ 1,714 करोड़
4.	आईआईटी- विक्रम उद्योगपुरी, मध्य प्रदेश - डीएमआईसी	1,100	₹ 808 करोड़
5.	आईएमएलएच-एनसी, हरियाणा - डीएमआईसी	886	₹ 1,029 करोड़ *(पीपीपी मोड)*
6.	एमएमएलएच -दादरी, उत्तर प्रदेश - डीएमआईसी	825	₹ 2,337 करोड़ *(पीपीपी मोड)*
	एमएमटीएच - बोराकी, उत्तर प्रदेश - डीएमआईसी	358	₹ 1,570 करोड़
7.	कृष्णापट्टनम, आंध्र प्रदेश - सीबीआईसी	2,006	₹ 2,139 करोड़
8.	तुमकुरु, कर्नाटक - सीबीआईसी	1,736	₹ 1,701 करोड़
9.	दिघी, महाराष्ट्र - डीएमआईसी	6,056	₹ 5,469 करोड़
10.	जेपीएमआईए, राजस्थान - डीएमआईसी	1,577	₹ 922 करोड़
11.	राजपुरा, पंजाब - एकेआईसी	1,099	₹ 1,367 करोड़
12.	खुरपिया, उत्तराखंड - एकेआईसी	1,002	₹ 1,265 करोड़
13.	हिसार, हरियाणा - एकेआईसी	2,988	₹ 4,680 करोड़
14.	आगरा, उत्तर प्रदेश - एकेआईसी	1,058	₹ 1,812 करोड़

15.	प्रयागराज, उत्तर प्रदेश - एकेआईसी	351	₹ 658 करोड़
16.	गया, बिहार - एकेआईसी	1,670	₹ 1,339 करोड़
17.	कोपार्थी, आंध्र प्रदेश - वीसीआईसी	2,595	₹ 2,136 करोड़
18.	ओरवाकल, आंध्र प्रदेश - एचबीआईसी	2,621	₹ 2,786 करोड़
19.	जहीराबाद, तेलंगाना - एचएनआईसी	3,245	₹ 2,360 करोड़
20.	पलक्कड़, केरल - सीबीआईसी एक्सटेंशन	1,710	₹ 3,805 करोड़
	कुल योग	**49,128**	**₹ 50,628 करोड़**

*****